भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3520

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

नए आईआईएम/एनआईटी

3520. श्री एस॰ मुनिस्वामीः

श्री तेजस्वी सूर्याः

श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य सहित देश में नए एनआईटी/आईआईएम शुरू करने के लिए स्थानों की पहचान की है और इन क्षेत्रों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) सरकार के पास तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को राज्यों से नए एनआईटी/आईआईएम स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): कर्नाटक के एक एनआईटी और आईआईएम सहित देश के विभिन्न भागों में पहले से ही संचालित 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और 20 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के अलावा कोई भी नया एनआईटी और आईआईएम खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग): सरकार ने अनेक जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), इम्पैक्टिटंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इम्प्रिंट), उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई), ग्लोबल इंनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) आदि पहलें शुरू की है जिसमें अंतनिर्हित तंत्र है, जो देश की गुणात्मक शिक्षा विकास की जांच करते हैं और उसे उपलब्ध कराते है। अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने नई संस्थाओं और वर्तमान संस्थाओं के अनुमोदन की स्वीकृति के लिए मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण, अनुसंधान और विश्वविद्यालयों, समवत विश्वविद्यालयों और कॉलजों में गुणवत्ता आश्वासन के लिए विनियमों, योजनाओं को बनाने और अधिसूचित करने एवं पात्र संस्थाओं को अनुदान देने के माध्यम से मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है।

(घ): तेलंगाना, पुद्दुचेरी और कर्नाटक राज्य में आईआईएम की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

*****